आखिर क्यों आक्रोशित है देश के पदक विजेता पहलवान...?

डॉ. विश्वास तिवारी

यह देश की खेल प्रतिभाओं के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है कि राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धाओं में पदक-जीतने वाली खेल प्रतिभाएं अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी है। यह रवैया कुश्ती महासंघ और खेल मंत्रालय के लिए सुखद नहीं है कि महासंघ के एक उच्च पदाधिकारी के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगे और देश के प्रतिष्ठित खेल प्रतिभाओं को धरने पर बैठना पड़े। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह जल्द से जल्द बाहर आनी चाहिए क्योंकि अब इस पर राजनीति होना शुरू हो गई है। एक और प्रियंका गांधी ने इनसे बातचीत की वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इनको संबोधित किया। इसके अलावा महिला किसान मोर्चा, महापंचायतों की खापों और किसान संयुक्त मोर्चा के राकेश टिकैत भी अपने दल बल के साथ इनका साथ देने को आ गए है। यानि यह तय है कि अब से ये मुद्दा गरमाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहुबली नेता और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष 66 वर्षीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। सिर्फ एफ.आर.आई. दर्ज करने में दिल्ली पुलिस का इतना समय लेना संदेह पैदा करता है। पांच बार भाजपा और एक बार समाजवादी पार्टी से सांसद रहे इस बाहुबली की गिरफ्तारी टालने का एक कारण 2024 का चुनाव भी हो सकता है। पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर इनकी बहुत पकड़ है। अपने साथ 10-12 लग्जरी कारों का काफीला लेकर चलने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर पहले भी कई दर्जन केस दर्ज है और यह कई बार जेल भी जा चुके है। दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को पनाह देने के जुर्म में यह टाडा के तहत जेल गए थे, तब इनका टिकट काट कर इनकी पत्नी को दे दिया गया था और वो भी गोंडा से चुनाव जीत गई थी।

देश के पहलवानों ने बृजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए है। यौन शोषण के अलावा उन पर तानाशाही और मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। पहलवानों ने यह भी कहा कि बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते है। बाहुबली सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों को कोर्ट के द्वारा 24 घंटे की पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व पहलवानों और पुलिस में देर रात झड़प हो गई थी। पहलवानों का आरोप था कि पुलिसकर्मी नशे में धुत थे इसलिए हाथापाई की नौबत आई। इस शिकायत पर पॉस्को एक्ट एंव छेड़खानी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई हैं जिसमें पांच वर्ष से लेकर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। पहलवानों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 2012 से 2022 तक छेड़खानी का आरोप लगाया है।

पहलवानों का कहना है कि उन पर धरना खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन धरना स्थल पर पानी, खाना, बिजली की आपूर्ति बाधित कर रहे है और उनके साथ आंतकियों जैसा व्यवहार कर रहे है।

वहीं बृजभूषण सिंह ने इस्तीफा देने से साफ इंकार कर दिया। उनका कहना है कि केवल एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा के दूसरे खिलाड़ी और दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ी उनका साथ क्यों नहीं दे रहे है?

देश के पहलवानों ने बृजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए है। यौन शोषण के अलावा उन पर तानाशाही और मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। पहलवानों ने यह भी कहा कि बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते है। बाहुबली सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों को कोर्ट के द्वारा 24 घंटे की पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व पहलवानों और पुलिस में देर रात झड़प हो गई थी। पहलवानों का आरोप था कि पुलिसकर्मी नशे में धुत थे इसलिए हाथापाई की नौबत आई।

उन्होंने कहा कि कुश्ती के ये बड़े सितारे केवल बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाने के लिए तैयार होते है और राष्ट्रीय प्रतिर्स्पाधा में भाग नहीं लेना चाहते है, जिससे दूसरे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे कांग्रेस और एक उद्योगपति का संरक्षण है जो उन्हें और उनकी संस्था को बदनाम करने के कोशिश कर रहे है। अगर उन्हें मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा कहेंगे तो वो इस्तीफा देने में एक मिनिट का समय भी नहीं लगाएंगे। वहीं धरना दे रहे खिलाड़ियों ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं होता है। देश के खिलाड़ियो का सम्मान होना जरूरी है और हम उसी सम्मान के लिए लड़ रहे है।

उन्होंने कहा कि बृजभूषण एक ताकतवर नेता है और बचने के लिए इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे है। राजनीति बाद में आती है पहले देश की बेटियों की इज्जत और सम्मान आता है। खिलाड़ियों ने देश के विभिन्न महिला संगठनों से उनका साथ देने की अपील भी की है। इस अपील के बाद कई क्रिकेटर और बॉलीवुड के सितारे भी उनके समर्थन में आगे आए है।

19 जनवरी, 2023 को पहलवान विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने जंतर-मंतर पहुंचकर रेंसलिग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद केंद्रीय खेलमंत्री अनुराग ठाकुर 23 जनवरी को दिग्गज मुक्केबाज मेरीकॉम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। इन्हें 4 हफ्तों में जांच पूरी करने को कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी, लेकिन इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

उधर सरकार इन खिलाड़ियों से इसलिए नाराज है क्योंकि इन बड़े पहलवानों ने दो बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया। फरवरी 2023 में कुश्ती के दो बड़े मुकाबले हुए। पहला क्रोएशिया में और दूसरा मिस्र में जिसमें रैंकिग अंक मिलते है, लेकिन हमारे कुश्ती के बड़े सितारों ने इसमें भाग नहीं लिया जिससे दूसरे पहलवानों को केवल 4 कांस्य पदकों से संतुष्ट होना पड़ा। खिलाड़ियों ने इस विवाद के चलते विश्व कुश्ती संघ को भी एक शिकायत की थी कि भारतीय संघ के अध्यक्ष ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है- जिसके चलते एशियाई चैम्पियनशिप की मेजबानी दिल्ली से छिनकर कजाखस्तान के दे दी गई है। सरकार का कहना है कि जब उन्होंने खिलाड़ियों की मांगे मान कर जांच कमेटी का गठन कर दिया था तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का बहिष्कार क्यों किया। अब कुश्ती संघ, खेल मंत्रालय और पहलवान आमने सामने आ गए है। खिलाड़ियों ने सरकार को 20 मई तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी का समय दिया है, उसके बाद यह सभी मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे।

हाल ही में उन्होंने ये मांग भी रखी है कि पूरे कुश्ती महासंघ को भंग कर दिया जाए और सांसद और उसके परिवार को इसके चुनाव से दूर रखा जाए।

सरकार को चाहिए कि ऐसे विवादों का जल्द से जल्द समाधान करे। ऐसे विवाद खिलाड़ियों की एकाग्रता और खेल को प्रभावित करते है और साथ ही भारत की खेल व्यवस्था की प्रतिष्ठता को भी धूमिल करते है। जब मैरी कॉम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि ये आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए गए है वर्ना हमारे देश के लोग अपनी बेटियों को खेलों में भेजने से पहले बार-बार सोचेंगे। यह आरोप सही है या गलत इसका फैसला तो होना ही चाहिए।

भारत में जनसंख्या प्रबंधन और नियंत्रण दोनों की जरूरत...

धीरज कुमार

भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में आगे निकल गया। भारत सहित दुनिया में इसपर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। भारत में समाज से लेकर सरकारों तक ने इसपर अपनी-अपनी चिंताए दर्ज की। और आश्चर्य नहीं कि आनेवाले समय में इसपर कोई बड़ी नीति भी सामने लाई जाए। जनसंख्या का विमर्श आधुनिक सदी का विमर्श है। प्राचीन समय से लेकर मध्य-काल तक जनसंख्या को लेकर कोई ऐसा विमर्श नहीं देखा गया जिसे तत्कालीन समय के एक संकट के रूप में देखा गया हो। यह मुख्य रूप से 19 वीं सदी से व्यापक विमर्श में आया। इसे दो सन्दर्भों में देखा जा सकता है- पहला, एक 'संसाधन' के रूप में, और दूसरा, एक 'खतरे' के रूप में।

'खतरे' के रूप में देखने का अर्थ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने राज्य के सामने अनगिनत समस्याओं को पैदा किया। इसमें शामिल था भूमि की कमी, भोजन और अन्य खाद्य सामग्री की कमी, अनगिनत महामारियां, नियोजन की दिक्कतें, आवास की कमी, और अनगिनत अन्य समस्याएं। इसपर नीति नियंताओं ने अलग-अलग तरह के प्रस्ताव दिए। एक समय में फैमिली प्लानिंग के तहत 'हम दो हमारे दो' का नारा भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में कुछ दशक पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानूनों का भी सहारा लिया गया। जिसमें बलपूर्वक नसबंदी तक शामिल थी। और जिसका जोरदार विरोध भी किया गया था। जिसका परिणाम तत्कालीन सरकार की 1977 के चुनावी हारों में भी देखा गया। 1975 में जब राज्य प्रायोजित सामूहिक बंध्याकरण(नसबंदी) प्रोग्राम चलाया गया था तो उसके भयावह नतीजें सामने आये थे। केवल एक वर्ष के भीतर करीब 6.2 मिलियन पुरुषों का बंध्याकरण कर दिया गया था। जिसमें से अनेकों की लापरवाही में हुए ऑपरेशन की वजह से मौतें भी हो गई थी। विज्ञान की पत्रकार मारा हीव्स टेएनडीह्ल के अनुसार, इस एक वर्ष में जितने पुरुषों के बंध्याकरण किये गए थे वह जर्मनी में नाजियों द्वारा करवाए गए बंध्याकरण से पंद्रह गुणा अधिक था।

इनके अलावा ऐसे भी विचार सामने आये जिसने जनसंख्या को एक सकारात्मक रूप में देखा। उन्होंने इसे एक 'संसाधन' के रूप में विचार करने पर बल दिया। यह माना गया कि यह आधुनिक पूंजी के युग में एक 'संसाधन' की तरह है। इसके समुचित प्रबंधन से राज्य की आर्थिक और सामरिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मतों को बहुत अधिक मान्यता तीसरी दुनिया में नहीं मिली।

सिक्योरिटी, टेरीटरी एंड पॉपुलेसन (1977-78) के व्याख्यान श्रृंखला में उत्तर के प्रख्यात चिन्तक मिशेल फूको इसपर बड़ा विमर्श लाते हैं। उन्होंने अपने विमर्श में 'भौगोलिक-राज्य' को 'जनसंख्या-राज्य' के अंदर समाहित करने की विचारधारा का मूल्यांकन किया। जनसंख्या आंकड़ों से संबंधित विमर्श को अधिक स्पष्ट तरह से राष्ट्रीय ताकत के साथ जोड़ कर देखा जाने लगा। और इसे चिकित्साविज्ञान, पुलिस, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के साथ जोड़ा गया। जनसंख्या वाले आंकड़ों ने जनसंख्या नियमितताओं और संसाधनों की उपलब्धता को उजागर किया। और फिर संसाधनों की राजनीति, राज्य की नीतियों के केंद्र में आ गया। जिसे भारत में आरक्षण आदि के मामलों में आसानी से समझा जा सकता है।

फूको बताते है कि जनसंख्या अंतिम लक्ष्य के रूप में सरकार के सभी अन्य लक्ष्यों से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। संप्रभुता के विपरीत, सरकार का उद्देश्य स्वयं सरकार के कार्य का नहीं होता है, बल्कि जनसंख्या के कल्याण, उसकी स्थिति को सुधारना, उसकी समृद्धि, लंबी आयु, स्वास्थ्य आदि का होता है। और सरकार द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय खुद जनसंख्या एवं उससे सम्बंधित पहलू में समाहित होते हैं। जनसंख्या पर विमर्श पोलिटिकल-इकॉनमी के साथ-साथ राज्य की नीतिगत संप्रभुता से जुड़ा मसला भी है। सुरक्षा, संसाधन का उचित वितरण, जनसंख्या में क्षेत्रीय संतुलन, रोजगार की उपलब्धता से सरे मसले शासन से जुड़े है एवं जिसे 'गवर्नमेंटालिटी' के सन्दर्भ में समझा जा सकता है।

इस अवधारणा को शासनव्यवस्था की अवधारणा के रूप में पहली बार फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको द्वारा 1978 और 1979 में कॉलेज डे फ्रांस में रखी गई व्याख्यानों की एक श्रृंखला में पेश की गई थी। इसे फ्रेंच शब्द %गवर्नमेंटल% से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 'सरकार के संबंध में'। हालांकि, फूको इसे 'व्यवहार की व्यवस्था% कहता है - जिसका अर्थ पश्चिमी उदार राज्य के नागरिकों पर नियंत्रण रखने के एक सेट के माध्यम से होता है, जैसे स्वतंत्रता, आत्म-पूर्ति, आत्म-विकास और आत्म-सम्मान। संक्षेप में, फूको सरकार की व्यवस्था के रूप में या 'व्यवहार की व्यवस्था' या 'शासन कला' के रूप में इसे परिभाषित करते हैं, जहां 'सरकार' एक विस्तृत नियंत्रण तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है जो विषयों को शासनयोग्य बनाती है। जनसंख्या का बढ़ना, उसका प्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं का आवंटन के साथ साथ जनसंख्या को नागरिक के तौर में देखते हुए इसे समुचित रूप से राष्ट्र निर्माण में प्रयुक्त करना, ये सभी राज्य का विषय बन जाता है।

भारत में यह पिछले कई दशकों से 'संसाधन' से अधिक एक बड़े 'संकट' के रूप में देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्ट इस तथ्य की और इशारा कर रहा है कि भारत में जनसंख्या दर घट रही है। वर्ष 2021 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.68 प्रतिशत तक गिर गई थी और अगर पाकिस्तान से तुलना करें तो, 2017 में जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत से ऊपर थी । साथ ही लेकिन आबादी का बढ़ना लगातार जारी है जो चिंताजनक है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह सच में एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अन्य अनगिनत देशों की तुलना में इसके संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या को देखे तो यह सुखद नहीं माना जा सकता है। पश्चिम के कई देश संसाधनों के मामले में जहाँ भारत से बहुत आगे हैं तो दूसरी तरफ जनसंख्या के मामले में बहुत पीछे।

ऐसी स्थिति में सरकार के पास कम से कम दो तरह से इसपर विचार करने के तरीके है- पहला इसके प्रबंधन से और दूसरा इसके नियंत्रण से। भारत में अबतक जो अधिकांश नीतियां रही है वह इसके नियंत्रण से सम्बंधित थी, लेकिन अनुभव से यह सामने आया कि इसका व्यापक जनविरोध हो सकता है। प्रबंधन का मतलब यहाँ जनसंख्या को संसाधनों के न्यायोचित वितरण से जोड़ना है। हालांकि, भारत जैसे विविध और संसाधन के अभाव वाले समाज में यह भी आसान कार्य नहीं है। ऐसे में प्रबंधन के साथ-साथ नियंत्रण की नीतियों से भी परहेज नहीं किया जा सकता।

मां बेटी के रिश्ते की सबसे खास बातें, बेटे भी नहीं कर पाते बराबरी

मदर्स-डे पर विशेष

एक मां और बच्चे का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। बच्चे के जन्म से पहले ही मां से उसका रिश्ता बन जाता है। जन्म के बाद शिशु के लिए मां का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बेटा हो या बेटी मां के साथ उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तो वह अपनी दुनिया में खो जाता है। उम्र के साथ बच्चा व्यस्तता के चलते अपने अभिभावकों से दूर हो सकता है लेकिन बेटी का रिश्ता वक्त के साथ मां के उतने ही करीब हो जाता है। बेटी का जन्म महिला को मां ही नहीं बल्कि एक दोस्त बना देता है।

दरअसल मां के लिए भले ही बेटा और बेटी एक हो, लेकिन बेटी उनका जीवन अधिक उत्साह बना सकती है। मां और बेटी के रिश्ते की पांच सबसे खास बातें हैं, जिसकी बराबरी एक बेटा भी नहीं कर पाता। आइए जानते हैं मां और बेटी के रिश्ते की सबसे खास बातें।

मां और बेटी की दोस्ती-मां और बेटी का सबसे खास रिश्ता उनके बीच की दोस्ती होती है। बड़े होने पर बेटी की पहली दोस्त माँ होती है। वहीं एक महिला शादी के बाद अपने दोस्तों से भले ही दूर हो जाएं लेकिन बेटी के जन्म के बाद मां के लिए वह उनकी परमानेंट दोस्त बन जाती हैं। वह दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कर सकती हैं। मां और बेटी के बीच की बातें सामान्यत:- एक जैसी होती हैं।

मां के सपनों का माध्यम-अक्सर शादी से पहले हर महिला के कुछ सपने होते हैं, जो वह अगर पूरा नहीं पाती तो अपने बच्चों से उसकी उम्मीद करती हैं। खासकर अगर महिला की बेटी होती है, तो उनकी उम्मीदें और अधिक बढ़ जाती हैं। अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मां बेटी पर निर्भर हो जाती हैं। ऐसे में बेटी भी अपनी मां के सपनों को सच करने का एक जरिया बन जाती है।

मां बेटी के बीच शेयरिंग-जब बेटी बड़ी हो जाती है तो मां के साथ अपनी चीजों को आसानी से शेयर कर सकती है। अक्सर बेटियां अपनी मां की साड़ी या ज्वेलरी को कैरी करती हैं, तो वहीं मां भी खास मौकों या ट्रिप पर बेटी के आउटफिट या मेकअप को अपना सकती हैं।

बातें शेयर करना-एक बेटी को दुनियादारी से लेकर घर परिवार संभालने तक हर बात के लिए उसकी मां सिखाती है। मां ही बेटी को उठने, बैठने और चलने का सलीका सिखाती है। जब बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जाने वाली होती है, तो उसे घर गृहस्थी की बाते मां ही सिखाती हैं।

मरीजों को राहत के लिए नीति बने

पंकज चतुर्वेदी

भारत की करीब 82.9 करोड़ वयस्क आबादी का 8.8 प्रतिशत हिस्सा मधुमेह की चपेट में है। अनुमान है कि सन् 2045 तक यह संख्या 13 करोड़ को पार कर जाएगी। मधुमेह वैसे तो खुद में एक बीमारी है लेकिन इसके कारण शरीर के खोखला होने की जो प्रक्रिया शुरू होती है उससे मरीजों की जेब भी खोखली हो रही है। साथ ही देश की मानव संसाधन कार्यक्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है। बीते एक साल में भारत के लोगों ने डायबिटीज या उससे उपजी बीमारियों पर सवा दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जो कि हमारे कुल सालाना बजट का 10 फीसदी है। बीते दो दशक के दौरान इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या में 65 प्रतिशत बढ़ोतरी होना भी कम चिंता की बात नहीं है।

एक अनुमान है कि एक मधुमेह मरीज को औसतन 4200 रुपये दवा पर खर्च करने होते हैं। इस बीमारी के कारण उसका सालाना औसतन अतिरिक्त व्यय 34100 रुपये हो जाता है। यह रोग ग्रामीण, गरीब बस्तियों और तीस साल तक के युवाओं को भी शिकार बना रहा है। मधुमेह जीवनशैली के बिगड़ने से उपजने वाला रोग है। भौतिक सुख जोड़ने की अंधी दौड़ तो खून में शर्करा की मात्रा बढ़ा ही रही है, कुपोषण, घटिया सड़कछाप व पेक्ड भोजन भी इसके मरीजों की संख्या में इजाफा करने का बड़ा कारक है।

बदलती जीवनशैली कैसे मधुमेह को आमंत्रित करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण लेह-लद्दाख है। भीषण पहाड़ी इलाका, लोग खूब पैदल चलते थे, जीविकोपार्जन के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती थी सो लोग कभी बीमार नहीं होते थे। पिछले कुछ दशकों में वहां बाहर का प्रभाव और पर्यटक बढ़े। उनके लिए घर में जल की व्यवस्था वाले पक्के मकान बने। बाहरी दखल के चलते यहां अब चीनी यानी शक्कर का इस्तेमाल होने लगा और इसी का कुप्रभाव है कि स्थानीय समाज में अब डायबिटीज जैसे रोग घर कर रहे हैं। एक सर्वे में यह तथ्य सामने आए हैं कि मधुमेह की चपेट में आए लोगों में से 14.4 फीसदी को किडनी और 13.1 को आंखों की रोशनी जाने का रोग लग जाता है।

इस बीमारी में 14.4 फीसदी मरीजों के पैरों की धमनियां जवाब दे जाती हैं जिससे उनके पैर खराब हो जाते हैं। वहीं लगभग 20 फीसदी लोग किसी न किसी तरह की दिल की बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। 6.9 प्रतिशत डायबिटीज लोगों को न्यूरो अर्थात तंत्रिका से संबंधित दिक्कतें भी होती हैं।

भारत को रक्त की मिठास बुरी तरह खोखला कर रही है। अमेरिकी मानक संस्थाओं ने भारत में रक्त में चीनी की मात्रा को कुछ अधिक दर्ज करवाया है जिससे प्री-डायबिटीज वाले भी इसकी दवाओं के फेर में आ जाते हैं। यह सभी जानते हैं कि एक बार डायबिटीज हो जाने पर मरीज को जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ती हैं। मधुमेह नियंत्रण के साथ-साथ रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं को लेना आम बात है। जब इतनी दवाएं लेंगे तो पेट में बनने वाले अम्ल के नाश के लिए भी एक दवा जरूरी है। जब अम्ल नाश करना है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कोई मल्टी विटामिन अनिवार्य है। एक साथ इतनी दवाओं के बाद लीवर पर तो असर पड़ेगा ही। मरीज हर महीने औसतन डेढ़ हजार की दवा या इंसुलिन तो लेता ही है, अर्थात? सालाना अठारह हजार।

देश के दूरस्थ अंचलों की बात तो जाने दें, राजधानी या महानगर में ही हजारों ऐसे लैब हैं जिनकी जांच की रिपोर्ट संदिग्ध रहती है। फिर गंभीर बीमारियों के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत पांच लाख तक के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था में मधुमेह जैसे रोगों के लिए कोई जगह नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जरता की बानगी सरकार की सबसे प्रीमियम स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस यानी केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा है जिसके तहत पत्रकार, पूर्व सांसद आदि भी आते हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों में चालीस फीसदी डायबिटीज के मरीज हैं और वे हर महीने केवल नियमित दवा लेने जाते हैं। एक मरीज की औसतन हर दिन की पचास रुपये की दवा।

एक मरीज डाक्टर के पास जाता है और उसे किसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। विशेषज्ञ कई जांच लिखता है और मरीज को फिर से अपनी डिस्पेंसरी में आकर जांच को इंडोर्स करवाना होता है। उसके बाद उसके अगले दिन खाली पेट जांच करवानी होती है। इस प्रकार मरीज को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ईमानदारी से तो डायबिटीज के मरीज को हर महीने विशेषज्ञ डाक्टर को पास जाना चाहिए। बहुत से मरीज इससे घबरा कर नियमित जांच भी नहीं करवाते। आज भारत मधुमेह को लेकर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। जरूरत है कि इस पर सरकार अलग से कोई नीति बनाए, जिसमें जांच, दवाओं के लिए कुछ कम तनाव वाली व्यवस्था हो। बाजार में मिलने वाले पेक्ड व हलवाई दुकानों की सामग्री की कड़ी पड़ताल, देश में योग को बढ़ावा देने के और अधिक प्रयास युवा आबादी की कार्यक्षमता और इस बीमारी से बढ़ती गरीबी के निदान में सकारात्मक कदम हो सकते हैं।